>

Title : Regarding large scale loss of crops due to Neelgai menace in Sitamarhi, Bihar.

**श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी):** महोदय, एक अति महत्वपूर्ण विषय जो पूरे देश के लिए और खासकर किसानों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय है, मैं उसकी तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। देश में जो मैदानी इलाके हैं और जो हिमालय का नीचे का भाग है, गंगा का जो कैचमेंट बेल्ट है, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर नील गायों की संख्या बढ़ रही है। इन नीलगायों के कारण यहाँ के किसानों की फसल बरबाद हो रही है। खासकर जहाँ मेरा क्षेत्र है - सीतामढ़ी, कहनानपुर और बोखरा प्रखंड में सैकड़ों की तादाद में नीलगाय उस इलाके की फसल को बरबाद कर देती है। जो हरी फसल है, इसके साथ-साथ आलू और ज़मीन में रहने वाली फसल को भी पैर से खरोंचकर बरबाद करते हैं और जब वहाँ के किसान इससे निजात पाने के लिए सरकारी अधिकारियों या पुलिस के पास जाते हैं तो कोई फायदा नहीं होता। सरकार के पास इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि उस नीलगाय से बचा जा सके।

हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं और बहुत सारे साथियों ने इस पर चर्चा भी की है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि इलाकों में भी बड़े पैमाने पर नीलगायों के उपद्रव से किसान परेशान हैं। हमारे इलाके का एक गाँव है। वहाँ के किसानों ने गाँव छोड़कर भागना शुरू कर दिया है क्योंकि उनके यहाँ फसल नहीं हो पाती है। जानीपुर गाँव में उनकी कोई फसल नहीं हो पाती है। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना पाई है कि उन नीलगायों को पकड़कर अच्छी जगह पर रखा जाए। अभी मैंने पढ़ा था कि जो मैदानी इलाके हैं, ग्रीनफील्ड्ज़ हैं, वहाँ नीलगाय रहती हैं, ये जंगल में रहना पसंद नहीं करते। ये लंबे समय से, 15-20 वर्षों से किसान की फसल को बड़े पैमाने पर बरबाद कर रहे हैं। एक तरफ तो कृषि महंगी होती जा रही है, फिर भी किसान फसल लगाते हैं परंतु नीलगाय उनको बरबाद कर देती हैं। किसी भी दृष्टि से ये नीलगाय उपयोगी नहीं हैं। लेकिन एक धार्मिक सैन्टिमैन्ट है हिन्दू समाज के लोगों में कि यह गाय की उपजाति है, भले ही उसकी उपजाति नहीं है और कोई इसको ह्रास भी नहीं करता। यह सवाल सदन में विभिन्न माध्यमों से उठता रहा है कि इस नीलगाय से किसानों को बचाने के लिए सरकार कोई ऐसा मैकेनिज़्म डैवलप करे, और जब तक कोई मैकेनिज़्म डैवलप नहीं होता, तब तक किसानों की जो फसल बरबाद होती है, उसको ऐसैस करके उन किसानों को मुआवज़ा देने के लिए कोई नया प्रावधान करे। हम सरकार से यह मांग करते हैं।